भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 6144
दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए

उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना

6144. श्री हरीभाई पटेल:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा संचालित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) का ब्यौरा और मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए प्राप्त आंकड़ों और घरेलू विनिर्माण तथ बिक्री में वृद्धि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) भारत सरकार द्वारा लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये के कुल अनुमोदित परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका उद्देश्य भारत के विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करना, निर्यात को बढ़ाना और देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। यह योजना एक निश्चित आधार वर्ष पर भारत में निर्मित वस्तुओं के वृद्धिशील उत्पादन/

बिक्री पर पात्र कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा माप, दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है। पीएलआई योजनाओं के तहत शामिल 14 क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

i. बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
ii. आईटी हार्डवेयर
iii. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद
iv. फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स
v. चिकित्सा उपकरण
vi. प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/दवा के घटक और रोग उपचार के लिए उपयुक्त मुख्य सामग्री
vii. ओटोमोबाइल एवं ऑटो घटक
viii. उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी
ix. कपड़ा उत्पाद: एमएमएफ परिधान एवं तकनीकी वस्त्र
x. खाद्य उत्पाद
xi. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल
xii. घरेलू विद्युत उपकरण (व्हाइट गुड्स) (एसी और एलईडी)
xiii. विशेष इस्पात (स्पेशियलिटी स्टील)
xiv. ड्रोन और ड्रोन घटक

(ख) एवं (ग) पीएलआई योजना क्षेत्र-विशिष्ट, अखिल भारतीय पहल के रूप में डिज़ाइन की गई है, और इस के लिए प्रोत्साहन राज्य-विशिष्ट होने के बजाय पात्र कंपनियों के वृद्धिशील उत्पादन/बिक्री और निष्पादन से जुड़े हैं। इस योजना से कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी हुई है।

दिनांक 31.12.2025 तक, पीएलआई योजनाओं के कारण 2.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है, 20.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धिशील उत्पादन/ बिक्री हुई है, और 8.49 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जिसमें संचयी प्रोत्साहन संवितरण 28,748 करोड़ रुपये हैं।

जबकि इस योजना ने देश भर में विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने में योगदान दिया है, उपलब्धियों का राज्य-वार मूल्यांकन केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

*****